

- संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया।
- लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के साथ ही संसद का मॉनसून सत्र सम्पन्न।
- कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू होगा।
- मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी-प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बरसात का दौर जारी।

000

संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगाएगा। विधेयक में ऑनलाइन मनी गेमिंग से संबंधित कानून का उल्लंघन करने पर तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए एक खतरा बन गया है। हर साल 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये गँवा देते हैं।

.....

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक का प्रदेश में भी स्वागत किया जा रहा है। अभिभावकों में इससे खुशी की लहर है। सवाईमाधोपुर की एक गृहिणी आशा शर्मा ने कहा कि सरकार के इस फैसले से समाज में गेमिंग की लत और वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा।

000

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के साथ ही संसद का मानसून सत्र सम्पन्न हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान 14 विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 12 विधेयक पारित हो गये हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए व्यवधानों के कारण सदन मुश्किल से 37 घंटे ही काम कर पाया। राज्यसभा के उपसभापित हरिवंश ने बताया कि सदन केवल 41 घंटे 15 मिनट ही चला और सत्र की उत्पादकता 38 दशमलव आठ प्रतिशत रही। स्थगन से पहले राज्यसभा ने आज तीन विधेयक संसद की संयुक्त समिति को भेज दिये हैं। इनमें 130वां संविधान संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक शामिल हैं।

000

प्रदेश में शिक्षा के समग्र विकास के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 3 हजार 200 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। केन्द्र से मिली इस राशि से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय में विभिन्न काम करवाए जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों में निर्माण और मरम्मत के काम होंगे। साथ ही स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल लैब और नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात कर ये राशि जारी करने का अनुरोध किया था। श्री शर्मा ने समग्र शिक्षा के तहत राज्य में शिक्षा विभाग की प्रगति, नीति और भविष्य में किये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को जानकारी दी थी।

000

राज्य के युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने के उद्देश्य से 'लैंग्वेज लैब' बनाई जाएगी। मानव संसाधन मंत्रालय और इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की ओर से ये लैब संचालित की जाएगी। इनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पैनिश, जापानी जैसी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लैंग्वेज लैब

के माध्यम से विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण से युवाओं के कौशल में बढ़ोतरी होगी। यह पहल युवाओं को पर्यटन, व्यापार, आईटी, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में रोजगार दिलाने में कारगर साबित होगी।

000

कोटा—बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस संबंध में आज नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक ली। इसमें केंद्रीय नागरिक उद्ययन मंत्री राममोहन नायडू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में श्री नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष को एयरपोर्ट परियोजना से जुड़ी प्रगति की जानकारी दी। परियोजना को लगभग दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2027 में इस हवाई अड्डे से पहली वाणिज्यिक उड़ान शुरू होने की संभावना है। श्री बिरला ने कहा कि ये एयरपोर्ट हाड़ौती अंचल के सामाजिक—आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। साथ ही नए रोजगार अवसर पैदा करेगा। एयरपोर्ट के डिजाइन में राजस्थान की पारंपरिक वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर को विशेष स्थान दिया जाएगा। इसके अलावा बैठक में मौजूदा कोटा एयरपोर्ट परिसर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से विशेष ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने का फैसला किया गया।

000

राज्य में शहरी और औद्योगिक गैस वितरण तंत्र—सीजीडी को विस्तृत करने के लिए जल्द ही केन्द्रीकृत वेब पोर्टल की सुविधा शुरू की जाएगी। खान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि इस पोर्टल पर राज्य में चल रहीं 13 सीजीडी संस्थाएं आवश्यक अनुमतियों के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगी। इसके साथ ही संबंधित संस्थाओं द्वारा अनुमतियां भी ऑनलाईन जारी की जाएंगी। ऑनलाईन व्यवस्था से मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव स्तर पर मॉनिटरिंग की जा सकेगी। साथ ही आवश्यक निर्देश जारी किये जा सकेंगे। इससे आधारभूत संरचना विकसित करने में देरी नहीं होगी। इसके साथ ही काम में पारदर्शित आएगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति, 2025 जारी की गई थी।

000

प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। लम्बे अंतराल के बाद में आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी जयपुर में रुक—रुक कर बरसात हुई। जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में दोपहर में झामाझाम बादल बरसे। सिरोही जिले के पिंडवाडा और स्वरूपगंज सहित कई इलाकों में बारिश हुई। सवाईमाधोपुर में हुई अच्छी बरसात से मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिली है। तेज बरसात से रणथंभौर दुर्ग और त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर पानी भरने से रास्ता बंद हो गया। वहीं पाली में तेज बारिश से कई जगह पानी भर गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

.....

बारां में जिला मुख्यालय सहित शाहबाद क्षेत्र में मूसलाधार बरसात हुई। इससे नेशनल हाईवे 27 पर यातायात प्रभावित रहा।

.....

मौसम विभाग ने आज 28 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, टोंक, अलवर और सीकर जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इन स्थानों पर तेज बरसात हो सकती है। एक दो दौर भारी बरसात के भी होने का पूर्वानुमान है।

000

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने आज चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और गिवअप अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री गोदारा ने जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए गिव अप अभियान को महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की सराहना करते हुए कहा कि जिले में अब तक 54 हजार से अधिक पात्र लोगों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाकर मिसाल पेश की है। श्री गोदारा ने अधिकारियों को नए लाभार्थियों को समय पर राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए, जिससे बिना किसी रुकावट के योजनाओं का लाभ मिल सके।

000

कृषि विभाग की ओर से प्रदेश में खाद की दैनिक उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए विभाग कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों और ब्लॉक्स की पहचान कर

वहां प्राथमिकता से डीएपी और यूरिया का वितरण कर रहा है। विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने बताया कि खरीफ 2025 सीजन में अप्रैल से अब तक 8 लाख 5 हजार मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की जा चुकी है। वहीं अब तक 3 लाख 25 मैट्रिक टन डीएपी किसानों को दिया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से राज्य को ये उर्वरक आंवटित किये गये थे।

000

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहनों से कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लिया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में, टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहनों से टोल वसूली के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित फर्जी खबरों पर यह स्पष्टीकरण दिया है। मंत्रालय के अनुसार नेशनल हाईवे ज पर दोपहिया वाहनों से टोल शुल्क वसूलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

000